भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति
26 फरवरी, 2022

साम्राज्यवादियों द्वारा यूक्रेन पर थोपे गए युद्ध रोकने आवाज बुलंद करें!
भारत के नागरिकों को स्वदेश लाने में सरकार की लापरवाही की भर्त्सना करें!

मानव जाति को विनाश की ओर ले जाने वाले साम्राज्यवादियों के बीच के अंतरविरोधों के तीव्र स्तर में पहुंचने के कारण अब युक्रेन पर युद्ध शुरू हो गया है. रूस और अमेरिका के बयानों से यह साफ है कि यह यहीं नहीं रुकेगा. दुनिया का हित चाहने वाले हर शख्स से हमारी केंद्रीय कमेटी यह मांग करती है कि वे युद्ध रोकने का नारा बुलंद करें. देश के सभी उत्पीड़ित वर्गों, सामाजिक तबकों, जनता एवं जनवादियों का आव्हान करती है कि वे यूक्रेन में मौजूद भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने की मांग करें.

यूक्रेन के पूर्वी रीजन में स्थित डोनेस्टेस्क, लूषन्सीव को स्वतंत्र सरकारों की मान्यता देकर रूसी संसद ने अपनी सेनाओं को वहां भेजने का निर्णय लिया जिससे साम्राज्यवादियों के बीच राजनीतिक, भौगोलिक व आर्थिक प्रतिद्वंद्विता खुलकर सामने आयी. रूस की सेनाएं न सिर्फ पूर्वी इलाकों में घुस गयी हैं बल्कि यूक्रेन पर सभी दिशाओं से हमले करते हुए राजधानी कीव पर भी हमले कर रही हैं. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद युरोप में फिर से उसी स्तर पर युद्ध का खतरा पहली बार मंडरा रहा है. इन परिणामों ने युरोप खासकर यूक्रेन की जनता को अनिश्चितता में धकेल दिया है. दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आयी. यूक्रेन में मौजूद 20 हजार से भी अधिक भारतीय असहाय बन डरे सहमे हुए हैं.

दुनिया में कच्चे तेल का भाव 110 डालर प्रति बैरल तक बढ़ गया है. उतना ही नहीं, आगामी कुछेक दिनों में यह भाव 150 डालर पार करने का अनुमान है. इस संकट के फलस्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी. आसमान छूते पेट्रोल, डीजल के भाव और भी बढ़ेंगे तथा सनफ्लावर आयल, गेंहुं, अल्यूमिनियम, मेटल की दरें बढ़ने वाली हैं.

1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तब रूस को अमेरिका ने जो हामी भरी थी, उसे फौरन बाद ही कूड़ेदान में फेंकते हुए नाटो का विस्तार करना शुरू किया. 12 देशों तक सीमित नाटो का अमेरिका ने अब 30 देशों तक विस्तार किया. वार्सा गठबंधन के पोलैंड, रुमेनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी को नाटो में शामिल किया. पांच साल बाद बाल्टिक देशों – एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया को भी मिला लिया. ये रूस से सटे हुए हैं. उसके बाद 2008 में जार्जिया, यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की अमेरिका ने घोषणा की. यदि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो मास्को के 500 मीटर तक नाटो की पहुंच हो जाएगी. अमेरिका अपने प्रक्षेपास्त्रों को यूक्रेन में तैनात करता है तो वह रूस के लिए काफी खतरनाक होगा. इससे ब्लैक सी(काला समुंदर) पर रूस का जो प्रभुत्व है, उसमें दरार पड़ेगा. अमेरिका अब भी यूक्रेन की सेनाओं को प्रशिक्षण, हथियार सहित नाटो सेनाएं भी उपलब्ध करा रहा है.

संभावित खतरे को देखते हुए एवं उन इलाकों पर अपने प्रभुत्व को कायम रखने के उद्देशय से रूस ने कुछ आक्रामक कदम उठाए. 2008 में जब जार्जिया में अंतःकलह छिड़ गए थे, उन्हें नियंत्रित करने सेना को उतारकर पुतिन ने उसे अपने नियंत्रण में लिया. यूक्रेन के क्रीमिया में विभाजनकारियों को सैनिक मदद देकर उसे रूस में मिला लिया. बेलारूस, काकसस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ–साथ मध्य एशियाई देशों में भी अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है.

यूक्रेन को जार के जमाने में ही रूस में शामिल किया गया था. सोवियत यूनियन में यूक्रेन स्वेच्छापूर्वक शामिल हुआ था. जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब यूक्रेन स्वतंत्र देश बना. तथापि यूक्रेन के पूर्वी रीजन में रूसी लोग अधिक संख्या में हैं. ये अपने इलाकों की आजादी की मान्यता के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं. यूक्रेन सरकार इन पर दमनात्मक कार्रवाइयां कर रही है. रूस की मदद् से ये यूक्रेन की सेनाओं को पलटा जवाब दे रहे हैं.

2014 में यूक्रेन ने इन सेनाओं को पीछे धकेल दिया. इस पर मध्य बेलारूस के मिंस्क में एक समझौता हुआ था. मिंस्क–1 समझौते पर अमल न कर फिर से उन इलाकों पर यूक्रेन ने हमला किया जिसे विद्रोहियों ने विफल किया और यूक्रेन की सेनाओं को हराया. इसके बाद फ्रांस, जर्मनी की मध्यस्थता के जरिए रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन के बीच मिंस्क–2 समझौता हुआ. इस समझौते के मुताबिक डोनेस्टेंस, लूषन्सीव को स्वायत्तशासी विशेष रीजन की मान्यता दी गयी थी. किंतु नाटो देशों के सहयोग से यूक्रेन इन देशों की स्वायत्तता को रोकता आ रहा है. दूसरी ओर नाटो में शामिल होने का निर्णय लिया. इससे वर्तमान युद्ध प्रारंभ हुआ.

यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद अमेरिका के नेतृत्व में फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन ने रूस पर कुंजीभूत आर्थिक प्रतिबंध लगाए. नार्थ स्टीम–2 पाइप लाईन को जर्मनी ने बंद किया. इससे रूस से गैस एवं तेल का आयात बंद हो गया. पश्चिमी देश कह रहे हैं कि रूस की प्रतिरक्षा जरूरतों, बैंकों, पुतिन के नजदीकी अरबपतियों पर आर्थिक प्रतिबंध अमल हो रहे हैं लेकिन ये प्रतिबंध सामान्य लोगों के कंधों पर असहनीय बोझ बनेंगे. पश्चिमी देश यह चाह रहे हैं कि इस तरह रूस संकट में फंस जाए. जबकि रूस यह तय कर लिया है कि चीन की मदद् से आर्थिक प्रतिबंधों को पार किया जाए.

प्यारे लोगों,

अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूसी साम्राज्यवादी देशों के बीच के चूहे–बिल्ली का खेल आखिर युद्ध का रूप लेकर दुनिया के लोगों खासकर युरोपीय देशों के लोगों को गंभीर कठिनाइयों का शिकार बना रहा है. दोनों विश्वयुद्धों एवं शीत युद्ध के दौरान विश्व मानव जाति अमन–चैन से दूर हो गया था. साम्राज्यवादियों के युद्ध पिपासू के

कारण करोड़ों लोगों ने जान गंवायी. वर्तमान युद्ध परिस्थितियां, तनाव मानव जाति को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे. आर्थिक व वित्तीय संकट जिसमें साम्राज्यवादी गले तक डूबे हुए हैं, से बाहर आने के लिए युद्धों में भिड़ रहे हैं. आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक प्रभुत्व की होड़ आखिर युद्धों के लिए रास्ता बना रहा हैं. दुनिया की समस्त जनता को चाहिए कि वह साम्राज्यवादियों एवं विश्व मानव जाति पर उनके द्वारा थोपे गए इस युद्ध का खंडन करे.

यूक्रेन पर हमले को फौरन रोककर पूर्वी रीजन के इलाकों से रूस को अपनी सेनाएं वापस बुलानी चाहिए. यूक्रेन सरकार को चाहिए कि वह तुरंत मिंस्क–2 समझौते पर अमल करे. यूक्रेन को नाटो में शामिल करना बंद करे. इन सभी इलाकों में निस्सैनिकीकरण पर अमल करना चाहिए.

भारत सरकार द्वारा एक ओर अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड जैसे सैनिक गठबंधन में सदस्य बने रहते हुए, दूसरी ओर रूस से प्रक्षेपास्त्र प्रणाली बना रही है. साथ ही यूक्रेन के मामले में शांति प्रवचन की लफ्फाजी, इस तरह वह साम्राज्यवादियों की युद्ध साजिश से बच नहीं सकता है. तमाम जनता को यह मांग करनी चाहिए कि भारत सरकार क्वाड से बाहर आए. यूक्रेन के मामले में युद्ध की अनिवार्यता को समझकर भी भारत सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही. ऐसे समय में भारत ने अपने दूतावास को वापस लाया जिसे नागरिकों की मदद में लगाना था. एअर इंडिया अपनी दरों को तीन गुना बढ़ाया है. सरकार ने यह घोषणा की कि भारत के नागरिकों को अपने खर्च से यूक्रेन से पड़ोसी देश पहुंचना चाहिए और वह वहां से उन्हें भारत लाने विमान सेवा उपलब्ध कराएगी. यह बहुत खर्चीला है. युद्ध के शुरू होने के बाद अपनाए गए कदम भारत के नागरिकों को स्वदेश लाने में समग्र नहीं हैं. भारत सरकार की इस लापरवाहीपूर्ण रवैए का विरोध करना चाहिए.

दुनिया के सभी देशों के मजदूरों, किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, राष्ट्रीयताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, शांति चाहने वालों सहित पूरी जनता का हमारी केंद्रीय कमेटी आव्हान करती है कि वे साम्राज्यवादियों द्वारा यूक्रेन में प्रारंभ किए गए युद्ध को तत्काल रोकने, जनता, इस धरती व दुनिया को बचाने के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद करे.

अभय

(अभय)
प्रवक्ता,
केन्द्रीय कमेटी,
भाकपा (माओवादी)